Statement

Details of the Control Room	Telephone No.
Delhi Development Authority	
1. Vikas Sadan, INA, New Delhi	621069
2. Slum Wing of DDA, Vikas Bhavan Annexe, I.P. Estate, New Delhi	3317632
Municipal Corporation of Delhi	
1. City Zone, Minto Road, New Delhi	3314511
2. Najafgarh Zone, Najafgarh, Delhi	5456375
3. New Delhi Zone, Ring Road, Lajpat Nagar, New Delhi	6854475
4. West Zone, Rajori Garden, New Delhi	593440
5. Shahdra Zone, Anaj Mandi, Shahdra, Delhi	2204381
6. Narela Zone, Narela, Delhi	7282536
7. South Zone, Green Park, N. Delhi	669552
8. Sadar Paharganj Zone, Idgah Road, New Delhi	777021
9. Karol Bagh Zone, Tibia College Building, New Delhi	528322
10. Civil Line Zone, 16, Rajpur Road, New Delhi	2923082
New Delhi Municipal Committee	
1. New Delhi Municipal Committee Control Room, Town Hall, New Delhi	351642 345606
Office of Deputy Commissioner, Delhi	
1. Room No. 154, First Floor, New Courts, Tis Hazari, Delhi	234835

राजस्थान में उचित दर की दुकानें

2297. **डा अबरार अहमद खान :** क्या खान और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) क्या सरकार उचित दर की दुकानों के माध्यम से गरीब लोगों को खाद्य सामग्री तथा कपड़ा उपलब्ध कराने की पद्धति में कोई सुधार करने और उनमें व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का विचार रखती है और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस समय देश में कितनी उचित दर की दुकानें हैं और राजस्थान में कितनी हैं तथा इनसे कितने व्यक्तियों को लाभ मिल रहा है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को समय-समय पर सलाह दी गई है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करें तथा सुव्यवस्थित बनाएं और इसके लिए वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य में लगी विभिन्न एजेंसियों के बीच कारगर तालमेल स्थापित करें, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सभी को राशन कार्ड जारी करें जहां आवश्यक हो और उचित दर की दुकानें खोलें, विशेषकर हरिजन बस्तियों, आदिवासी क्षेत्रों आदि में ये दुकानें खोली जाएं, दूरस्थ, पहाड़ी रेगिस्तानी तथा दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आवश्यक वस्तुएं सप्लाई करने के लिए चलती-फिरती दुकानें चलाएं, प्रवर्तन और

निरीक्षण प्रबन्धों को कड़ा कर करें, उचित दर दुकानों के कार्यकरण पर निगरानी रखने के लिए सलाहकार/सतर्कता समितियां गठित करें आदि । समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष रूप से राज-सहायता युक्त खाद्यान्न सप्लाई करने की एक योजना पहले से ही चल रही है । तथापि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रशासन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है ।

(ख) देश में 3.5 लाख से अधिक उचित दर की दुकानें हैं । राजस्थान में इनकी संख्या 14647 है, जो लगभग 3.4 करोड़ आबादी की सेवा कर रही है ।

Ticketless passengers

2298. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the number of ticketless rail travellers in the country is increasing manifold since the present Government have taken over;

(b) whether the machinery to detect the ticketless rail travellers has also failed to detect such cases in the trains; and

(c) if so, what other steps Government propose to take to stop ticketless rail travelling in the country?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) and (b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Miraj-Bangalore Railway Line

2299. SHRI H. HANUMANTHAPPA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether conversion of Miraj-Bangalore Railway line will be taken up during Eighth Plan; and

(b) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) Specific Gauge Conversion proposals to be taken up during the Eighth Plan have not been identified;

(b) Does not arise.

असिंचित भूमि से कृषि उत्पादन

2300. **सरदार हरजीत सिंह अरोड़ा :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश की कुल कृषि भूमि का 70 प्रतिशत भाग सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर करता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस भूमि से कृषि उत्पादन देश की सिंचित भूमि के कृषि उत्पादन के आधे से भी कम है ;

(ग) क्या सरकार ने इस भूमि से होने वाले प्रति हैक्टेयर उत्पादन का अनुमान लगाया है ;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और भविष्य में इस प्रकार की भूमि से उत्पादन दर बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ; और

(ङ) ऐसे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपनाए गए कार्यक्रम की रूप रेखा क्या है?

उप प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) 1986-87 (नवीनतम उपलब्ध) के भू-उपयोग सांख्यिकी आंकड़ों के आधार पर देश में कुल अ-सिंचित क्षेत्र लगभग 69 प्रतिशत है ।

(ख) सिंचित और असिंचित क्षेत्रों के लिए कृषि उत्पादन का अलग से अनुमान नहीं लगाया जाता ।

(ग) से (ङ) प्रमुख राज्यों द्वारा असिंचित क्षेत्रों के लिए प्रति हैक्टेयर